



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श०)

(सं० पटना 537) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

सं० 08/आरोप-01-122/2014-4932-सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

25 अप्रैल 2017

श्री रामेश्वर रविदास, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1867/99, 965/04 के विरुद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, चैनपुर (भभुआ) के पदस्थापन काल में योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी राशि के दुर्विनियोग/वित्तीय अनियमितता/वित्तीय प्रावधानों की अवहेलना तथा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) द्वारा प्रतिवेदित किया गया। विभागीय आदेश संख्या-10495, दिनांक 18.12.1997 द्वारा श्री रविदास को निलंबित किया गया तथा उक्त आरोपों की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-3994, दिनांक 15.04.1998 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में विभागीय आदेश सं०-833, दिनांक 08.02.2003 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री रविदास से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री रविदास से स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। जिसकी समीक्षा एवं आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-12155, दिनांक 18.11.2008 द्वारा श्री रविदास को “सेवा से बर्खास्तगी” का दंड संसूचित किया गया।

2. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री रविदास ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका (सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-18934/08) दायर किया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2013 को पारित आदेश के क्रम में श्री रविदास ने पुनर्विलोकन आवेदन समर्पित किया, जिसे समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7235, दिनांक 30.05.2014 द्वारा अस्वीकृत करते हुए सेवा से बर्खास्तगी संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक-12155, दिनांक 08.11.2008 को यथावत् रखा गया।

इसके पश्चात् श्री रविदास ने पुनः माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर स्वयं के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही, सेवा से बर्खास्तगी एवं अपने पुनर्विलोकन आवेदन को खारिज किये जाने संबंधी निर्गत विभागीय आदेशों की वैधता को चुनौती दी। एतदसंबंधी सी०डब्ल्यू०जे०सी०सं०-14323/14 में दिनांक 04.03.2016 को न्यायादेश पारित हुआ। जिसके अनुपालन में श्री रविदास ने सामान्य प्रशासन विभाग में अपना योगदान (दिनांक 20.04.2016) समर्पित किया। विभागीय स्तर पर उक्त न्यायादेश के अनुपालन में समीक्षोपरांत संकल्प ज्ञापांक-7077, दिनांक 18.05.2016 द्वारा श्री रविदास की सेवा बर्खास्तगी संबंधी विभागीय संकल्प (ज्ञापांक-12155, दिनांक 18.11.2008) एवं द्वितीय कारण पृच्छा संबंधी पत्र (पत्रांक-7268, दिनांक 16.07.2007) को वापस ले लिया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (5) के तहत बर्खास्तगी की तिथि (दिनांक 18.11.2008)

के प्रभाव से श्री रविदास को पुनः निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय तथा उनके जीवन-यापन भत्ता की आदेयता का निर्धारण किया गया। इसके साथ ही नये सिरे से अग्रेतर कार्रवाई के क्रम में विभागीय पत्रांक-7292, दिनांक 20.05.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री रविदास से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री रविदास द्वारा दिनांक 13.06.2016 को समर्पित लिखित अभिकथन में स्वयं को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया। योजना में अनियमितता के विन्दु पर आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध दर्ज चैनपुर थाना कांड सं०-46,55,56,57,58 एवं 59/97 के संबंध में पुलिस अधीक्षक, कैमूर के पत्रांक-1787, दिनांक 03.06.2016 द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।

अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा स्पष्टीकरण) की गहन समीक्षा के उपरांत आरोपों की प्रमाणिकता के आलोक में दंड (अनिवार्य सेवानिवृत्ति) विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य प्राप्त किया गया। इस क्रम में प्राप्त सहमति के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1410, दिनांक 06.02.2017 द्वारा श्री रविदास को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड संसूचित किया गया।

3. उक्त दंडादेश की कंडिका 9 के अनुपालन में श्री रविदास के निलंबन अवधि (दिनांक 18.12.1997 से दिनांक 08.02.2003 एवं दिनांक 18.11.2008 से दिनांक 06.02.2017) के वेतन भुगतान हेतु विभागीय पत्रांक-2122 दिनांक 21.02.2017 द्वारा कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री रविदास का स्पष्टीकरण (दिनांक 20.03.2017) प्राप्त हुआ है। अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने लम्बी अवधि तक विभागीय कार्यवाही के प्रक्रियागत रहने तथा इस क्रम में पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक निलंबित रहने के कारण आर्थिक संकट से ग्रस्त होने का उल्लेख किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि विभागीय कार्यवाही में उन्हें न्याय नहीं मिला।

आरोप, जाँच प्रतिवेदन, दंडादेश एवं श्री रविदास से प्राप्त कारण पृच्छा (स्पष्टीकरण) की गहन समीक्षा के आधार पर निलंबन अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य नहीं पाया गया।

4. अतएव सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1410 दिनांक-06.02.2017 द्वारा पारित दंडादेश के क्रम में श्री रामेश्वर रविदास के निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निम्नवत आदेश पारित किया जाता है:-

- (i) निलंबन अवधि (दिनांक 18.12.1997 से दिनांक 08.02.2003 एवं दिनांक 18.11.2008 से दिनांक 06.02.2017) मात्र पेंशन प्रयोजनार्थ सेवावधि के रूप में मानी जायेगी।
- (ii) निलंबन अवधि के लिए श्री रविदास को उक्त अवधि के लिए देय वेतन का 75 प्रतिशत ही देय होगा जिसमें से भुगतान की गयी राशि घटाते हुए शेष राशि का भुगतान होगा।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)537+571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>